ड्रग्स-हथियार तस्करी नेटवर्क की परतें खुलीं

औबेदुल्लागंज के व्यापारी का बेटा अमन गिरफ्तार, देशी पिस्टल और जिंदा राउंड बरामद

भोपाल,6 अगस्त. राजधानी में ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. गुप्त सूचना के आधार पर औबेदुल्लागंज निवासी एक बड़े व्यापारी के बेटे अमन को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा राउंड जब्त किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार अमन किसी गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था. प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि यह हथियार उसने लगभग तीन महीने पहले अंशुल उर्फ भूरी से खरीदा था, जो कुख्यात तस्कर यासीन मछली के लिए काम करता है. यासीन ड्रग्स और हथियार तस्करी के एक बड़े गिरोह का सरगना है, जिसका नेटवर्क धीरे-धीरे उजागर हो रहा है.

> क्राइम ब्रांच ने अमन के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1ए) के तहत केस दर्ज कर लिया है. साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि अमन के खिलाफ भोपाल के विभिन्न थानों में पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब अमन से पूछताछ कर ड्रग्स और हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से राजधानी में सक्रिय माफिया नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है. अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है.

गोविंदगढ़ और बेंगलुरु के बीच मंथन

बाघ संरक्षण में सहयोग बढ़ेगा : उप मुख्यमंत्री

भोपाल, 6 अगस्त. राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में आयोजित बैठक में रीवा जिले के गोविंदगढ़ स्थित बाघ प्रजनन केन्द्र और कर्नाटक के मंगलुरु स्थित पीलीकुला बायो लॉजिकल पार्क के बीच प्रस्तावित वन्यप्राणी आदान-प्रदान योजना की समीक्षा की.

बैठक में अपर मुख्य सचिव, वन अशोक बर्णवाल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन भी उपस्थित रहे. शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत कर रहा है. गोविंदगढ़ बाघ प्रजनन केन्द्र में संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं. उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सहयोग बेहद आवश्यक है. इसके लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्रस्तावित आदान-प्रदान प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंदगढ़ बाघ प्रजनन केन्द्र को वन्यजीव पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण एवं अनुसंधान के एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना, विशेषज्ञ संसाधन और तकनीकी मार्गदर्शन की रूपरेखा तैयार की जाए. गोविंदगढ़ बाघ प्रजनन केन्द्र बाघ संरक्षण की दिशा में प्रदेश की एक महत्त्वपूर्ण पहल है.

मलिक के निधन और उत्तराखंड हादसे में हताहतों को दी श्रद्धांजलि

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, सदन में बुधवार को निधन उल्लेख के दौरान पूर्व राज्यपाल और केंद्रीय राज्यमंत्री सत्यपाल मलिक और उत्तराखंड के धराली गांव में पानी के सैलाब से पूरे गांव के ही प्रभावित होने से जान-माल के भारी नुकसान की घटना पर सदन ने संवेदना व्यक्त की और दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी.

दिवंगतों के सम्मान में सदन में दो मिनट का मौन रखा गया. बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई, इस कारण प्रश्नकाल भी नहीं हो सका. विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने निधन उल्लेख के दौरान पूर्व राज्यपाल मलिक और उत्तराखंड के धराली गांव में हुए हादसे का जिक्र किया. उसके बाद उन्होंने अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी मलिक से जुड़े संस्मरणों को याद किया वहीं उत्तराखंड हादसे को लेकर कहा कि प्रकृति की लीला प्रकृति ही जाने. उन्होंने कहा कि हादसे में किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. उन्होंने पूर्व में केदारनाथ हादसे का भी जिक्र किया. सीएम ने कहा कि उनकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में रहे कोई कमी

संभागायुक्त सिंह ने बैठक में दिए निर्देश

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 06 अगस्त. स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर आयोजित होगा. समारोह की व्यवस्थाओं की तैयारी के लिए संभागायुक्त संजीव सिंह, कमांडेंट 7वीं वाहिनी हितेश चौधरी एवं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने समीक्षा की.

संभागायुक्त सिंह ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि समारोह की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए. सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाएं. कमांडेंट 7वीं वाहिनी चौधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बारी-बारी से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि समारोह में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, छात्र-छात्राओं एवं आमजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. समारोह स्थल पर पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश और बैठक व्यवस्था बेहतर हो. ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए. स्कूली बच्चों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था कर ली जाए. उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े.

> चौधरी ने कहा कि समारोह स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, शौचालय की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. उन्होंने कहा कि संस्कृति विभाग द्वारा प्रातः काल शौर्य स्मारक एवं सायंकाल रविंद्र भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारी कर ली जाए. समारोह स्थल पर स्वास्थ्य विभाग टीम एवं फायर ब्रिग्रेड की उपलब्ध रहे.

बड़े तालाब से जलकुंभी की करें सफाई

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 06 अगस्त. निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने बड़े तालाब में जलकुंभी सफाई कार्य का निरीक्षण किया.

राजा भोज प्रतिमा के आसपास सहित संपूर्ण तालाब क्षेत्र से जलकुंभी की सफाई बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. निगम आयुक्त करबला पम्प हाउस सहित अन्य स्थान का दौरा किया. तालाब में एकत्र जलकुंभी और उसे निकालने के कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की. निगम आयुक्त नारायन ने कहा कि जलकुंभी सफाई के उपरांत तालाब क्षेत्र में सतत् रूप से निगरानी भी की जाए और वर्षा के दौरान बहकर आने वाली जलकुंभी को तत्काल साफ करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए.

अजा-जजा की जमीनों पर दबंगों का कब्जा : राजेंद्र

जिलाध्यक्ष जगन्नाथ ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

भोपाल, 6 अगस्त. मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन में मुख्य वक्ता और अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मप्र में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को कांग्रेस सरकार ने पट्टे दिए थे, जिन पर दबंगों ने कब्जा जमा रखा है.

कई गांवों में इस वर्ग के लोगों को जमीनों से बेदखल कर दिया है. एक प्रकार से यह वर्ग भारी संकट के दौर से गुजर रहा है. इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेताप्रतिपक्ष उमंग सिंगार, विदिशा के जिलाध्यक्ष जगन्नाथ अहिरवार समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम का ऐतिहासिक धरोहर की तस्वीर सौंपकर स्वागत किया. जगन्नाथ अहिरवार ने बताया कि मध्य प्रदेश में पट्टे वालों की जमीनें दबंगों द्वारा बलपूर्वक छीनी जा रही हैं.

> प्रदेश में गंभीर घटनाएं घटित हो रही हैं, उस पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाए. अहिरवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि शासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे प्रदेश बड़ा आंदोलन किया जाएगा. न्याय सम्मेलन में मुख्य रूप से अनीश मंसूरी, संतोष अहिरवार, मनमोहन अहिरवार, दिनेश अहिरवार, अकबर पठान, राकेश आदिवासी, लक्ष्मण मालवीय, वीर सिंह, राजकुमार बुंदेल, रति वाई, सौदान आदिवासी, वीरेंद्र सिंह आदिवासी, विजय सहरिया, जगदीश सहरिया आदि उपस्थित रहे.

रानी कमलापति से रीवा के लिए विशेष ट्रेन

भोपाल. रेलवे ने रक्षाबंधन पर्व यात्रियों को खास सौगात दी है. रानी कमलापति-रीवा-मध्य एक-एक ट्रिप की एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इस स्पेशल ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान तथा सामान्य श्रेणी के कोच सम्मिलित रहेंगे, जिससे सभी वर्गों के यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सकेगी. यह ट्रेन दोनों दिशाओं में विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर एवं सतना स्टेशनों पर ठहरते हुए गंतव्य तक जाएगी. यात्रा के लिए आरक्षण रेलवे के किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र या आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से कराया जा सकता है.

लाला परेड मैदान में रिहर्सल के दौरान कदमताल करते जवान

भोपाल. लाला परेड मैदान में 15 अगस्त से पूर्व जवानों की रिहर्सल शुरू हो गई है. बुधवार को जवानों ने कदमताल करते हुए रिहर्सल की.

स्मार्ट मीटर वालों को 1 .08 करोड़ की छूट

टाइम ऑफ डे टैरिफ के तहत 20 प्रतिशत की रियायत

भोपाल, 6 अगस्त . मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर क्षेत्रों के 1 लाख 24 हजार 701 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को जुलाई माह में बिजली बिल पर कुल 1.08 करोड़ की छूट दी गई है.

यह छूट टाइम ऑफ डे टैरिफ योजना के तहत दी गई, जिसमें उपभोक्ताओं को दिन के समय खपत की गई बिजली पर 20 प्रतिशत की रियायत दी जाती है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, स्मार्ट मीटर वाले घरेलू, गैर-घरेलू, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक जल कार्य और निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को 10 किलोवाट तक की स्वीकृत लोड श्रेणी में यह लाभ मिला है. इस छूट में किसी प्रकार की सरकारी सब्सिडी को शामिल नहीं किया गया है. कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया कि भोपाल क्षेत्र में 1,16,736 उपभोक्ताओं को 1 करोड़ से अधिक की छूट दी गई, जबकि ग्वालियर क्षेत्र में 7,965 उपभोक्ताओं को 8.14 लाख की राहत मिली. उपभोक्ताओं को यह छूट उनकी खपत के आधार पर 50 से 12,160 तक दी गई.

स्मार्ट मीटर से पारदर्शिता और सुविधा

प्रबंध संचालक ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगवाने में सहयोग करें. उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी प्रणाली है, जिसमें सटीक रीडिंग और बिलिंग होती है. यह मीटर मोबाइल एप के माध्यम से रियल-टाइम में खपत दिखाता है, जिससे उपभोक्ता ऊर्जा की बचत कर सकते हैं. स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रबंधन में सशक्त बनाते हैं और ऊर्जा की खपत कम कर पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर डालते हैं. उपभोक्ता मोबाइल एप के जरिए कहीं से भी खपत पर नजर रख सकते हैं.

ठेले, काउंटर, टेबिल, कुर्सियां सहित सामान भी किया जब्त

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 06 अगस्त. नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार को कार्यवाही की. सड़कों, फुटपाथों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रखे सामान, कबाड़ा, अवैध छप्पर को हटाया गया.

इस दौरान नालियों पर अवैध फर्शियां, छज्जे पानी की टंकी, ठेले, टेबिल, बैग सहित को हटाया गया. अमले ने ठेले, काउंटर, टेबिल, कुर्सियां, लोहे की जाली, गैस सिलेंडर, भट्टी, पन्नी आदि सहित अन्य प्रकार का सामान भी जब्त किया. निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने को कोलार, सर्वधर्म कालोनी, चूना भट्टी, ललिता नगर, रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन, भाजपा प्रदेश कार्यालय, गौतम नगर, बिट्टन मार्केट, बागसेवनिया समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई की.

झांकी-पंडाल के लिए लें अस्थाई कनेक्शन

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 06 अगस्त. गणेशोत्सव त्यौहार सहित त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी बिजली कनेक्शन देने के लिए कंपनी ने प्रबंध किए हैं.

कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें. बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं, आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें, रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएं, आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें, विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी, झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें.

> अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका, पारेषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना, अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही, अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही.

अनदेखी ▶ सतनामी नगर में 10 करोड़ कीमती जमीन पर 15 साल से कब्जा

राजधानी में सत्ता के संरक्षण में अतिक्रमण का जाल

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 06 अगस्त. राजधानी के अलग-अलग इलाकों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. हाई कोर्ट के आदेशों और प्रशासनिक नोटिसों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही. इस लापरवाही से जहां आम लोगों में रोष है, वहीं कानून के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे है.

गोविंदपुरा क्षेत्र के सतनामी नगर में 10 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी जमीन पर करीब 30 अवैध दुकानें बना ली गई. आरोप है कि भाजपा समर्थक नेताओं ने कब्जा कर यह दुकानें 5-5 लाख रुपये में बेच दी. 2011 में हाई कोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद 4 अलग-अलग एसडीएमों ने 5 बार नोटिस जारी किए, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई. पिछले महीने 21 जुलाई को फिर एक नोटिस जारी हुआ, जिसमें 29 जुलाई तक कार्रवाई की चेतावनी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

गांधी नगर स्थित आसाराम आश्रम में अवैध निर्माण तोड़ने राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन बच्चों के विरोध के चलते कार्रवाई रोक दी गई. अधिकारियों ने कार्य मे बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है, लेकिन असली सवाल यह है कि कार्रवाई अधूरी क्यों छोड़ी गई? मई और जुलाई 2025 के बीच प्रशासन ने गोविंदपुरा, छावनी पठार, मयूरी गार्डन, श्री श्याम सिटी और मुस्कान सिटी जैसी अवैध कॉलोनियों को हटाया. करीब 12.5 करोड़ की जमीन खाली कराई गई, लेकिन सतनामी नगर जैसे उदाहरण प्रशासन की पक्षपाती कार्यशैली को उजागर करते है.

> ### अरेरा कॉलोनी में कमर्शियल अतिक्रमण
>
> अरेरा कॉलोनी के ई-1 से ई-5 सेक्टर में अब तक करीब 60 मकानों में बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं. मेन रोड ही नहीं बल्कि कालोनी के भीतर भी करीब 15 फीसदी मकानों में छोटे-बड़े व्यावसायिक बाजार हो रहा है. नगर निगम ने दो साल पहले नोटिस तो दिए थे, लेकिन मामूली कार्रवाई के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया.

बड़े कब्जाधारियों पर बुल्डोजर के पहिए नहीं घूमते

स्थानीय लोग अब पूछ रहे हैं कि जब छोटे दुकानदारों या गरीबों की झुग्गियों पर बुल्डोज़र चल सकता है, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अवैध कब्जाधारियों पर क्यों नहीं? अतिक्रमण से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ा है.

जल निकासी प्रभावित हो रही है और बुनियादी सुविधाओ पर बोझ पड़ रहा है. प्रशासन को अब यह तय करना होगा कि वह न्याय करेगा या राजनीतिक दबाव मे खामोश रहे.

ट्रेनी 27 डिप्टी कलेक्टर का कमिश्नरेट में भ्रमण

भोपाल. मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी में 4 अगस्त से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल प्रदेश के 27 डिप्टी कलेक्टर्स ने बुधवार को भोपाल कमिश्नरेट का भ्रमण कराया गया. इस अवसर पर पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा सभी डिप्टी कलेक्टरों से संवाद किया गया. साथ ही कानून व्यवस्था ड्यूटी तथा विपरीत परिस्थिति में पुलिस एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण दायित्वों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सारगर्भित मार्गदर्शन दिया गया. उपरांत सभी डिप्टी कलेक्टर ने सीसीटीवी सर्विलांस, पुलिस कंट्रोल रूम एवं महिला थाने का भ्रमण किया एवं पुलिस कार्रवाई से रूबरू हुए.

सेवानिवृत्ति आयुसीमा में समानता की जाए, एसीएस से मिले कर्मचारी

भोपाल, 6 अगस्त. राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के प्रांताध्यक्ष शील प्रताप सिंह पुंढीर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला से मुलाकात की और उनके समक्ष मुद्दे रखे.

संघ के प्रांताध्यक्ष पुंढीर ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को सीपीसीटी, स्टाइपेंड, सेवानिवृत्ति आयुसीमा में समानता समेत अन्य मांगे वर्षों से लंबित हैं, जिनका शासन स्तर पर निराकरण नहीं हो पा रहा है. खास तौर पर सेवानिवृत्ति की आयु-सीमा में अंतर होने से कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश पनप रहा है.

इससे सरकार की छबि पर धूमिल हो रही है. जिसका असर शासन के काम पर भी पड़ रहा है. जिसको शासन हल्के में न ले. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने उक्त मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है. प्रतिनिधि मंडल में सियाराम नेगी, प्रणव खरे, संजीव संतानी सहित संगठन अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे.